



2026:AHC-LKO:42332

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4858 वर्ष 2026

राधिका

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : जयकरण

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें भा०न्या०सं०, 2023 की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 315, 61(2) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 569/2025, थाना कोतवाली नगर, जिला – रायबरेली में मुकदमे के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान अधिवक्ता निर्दोष है और उसे किसी स्वार्थवश इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि बैंक मैनेजर द्वारा दर्ज कराई

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में 48 आरोपियों के नाम हैं, लेकिन आवेदक का नाम नहीं है। उनका कहना है कि आवेदक 45 वर्षीय महिला है और वह अपने पति के साथ जेल में है। उन्होंने बताया कि आवेदक किसी भी अपराध में शामिल नहीं थी और ऐसा लगता है कि बैंक में उसके दस्तावेज़ का इस्तेमाल करके उसे बलि का बकरा बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 9 अप्रैल 2026 से जेल में है। उनका कहना है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि बैंक प्रबंधक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में 48 आरोपियों के नाम हैं, लेकिन आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक 45 वर्षीय महिला हैं और वे अपने पति सहित जेल में हैं। आवेदक 9 अप्रैल 2026 से जेल में बंद हैं और जैसा कि जमानत आवेदन के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट किया गया है, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक ने वचन दिया है कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे इसका दुरुपयोग नहीं करेंगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभियोग की प्रकृति और दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, अभियोग के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का उपयुक्त मामला पाता हूं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **राधिका** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- 1) आवेदक विवेचना या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (2) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत कार्यवाही कर सकती है;
- (3) आवेदक को मुकदमे की शुरुआत, अभियोग निर्धारण और धारा 313 दं०प्र०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा; और
- (4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निपटारे तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जून 30, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।